

व्यावसायिक शिक्षा में कौशल विकास Skills Development in Vocational Education

डॉ. निशु सिन्हा

(सहायक प्राध्यापक (अतिथि) एस.पी.एम. कौलेज, उदन्तपुरी, बिहारशरीफ, बिहार, नालन्दा)

(Received:25 February2023/Revised:14March2023/Accepted:20March2023/Published:31March2023)

सार (abstract)

व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा किसी खास विषय या क्षेत्र में महारत हासिल की जाती है। पहले बड़े ही सीमित अवसर होते थे, रोजगार पाने के कारपेन्ट्री, वेल्डिंग आटो-मोबाइल जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारे नये-नये क्षेत्रों का विकास हो गया है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, टूरिस्ट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कम्प्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट, रिटेल ट्रेनिंग मैनेजमेंट, टूर एण्ड ट्रवल्स मैनेजमेंट इत्यादि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जिसमें आय निपुण होकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कुशल हाथ ही एक नये और बेहतर कल का रचयिता हो सकता है। जब हर हाथ में हुनर होगा, तभी हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो पाएगा। सबसे बेहतर वक्त में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूरा करने और समावेशी और संतुलित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह शिक्षा जरूरी है। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल विभाजन की भी चुनौतियों से पार पाना होगा और अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग और जीवन पर्यन्त, लर्निंग के लिए समान अवसर पैदा करने होंगे। कौशल क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी। यह संभव हो जाने से व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यों और कुशल श्रमशक्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके कारण भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के एजेंडा को बल मिलेगा।

चूँकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के साथ परिवर्तन होते हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की शिक्षा, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा परिवर्तन होते हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की शिक्षा, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में मानव संसाधन के रूप में विकास में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य कार्यकुशल

नहीं बन सकता। कार्यकुशलता के बिना व्यावसायिक एवं आर्थिक सफलता की प्राप्ति नहीं की जा सकती हैं।

समय समय पर शिक्षा को अधिकउपयोगी एवं इसके उद्देश्यों को अधिक सार्थक बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन किया गया।

लगभग सभी शिक्षा आयोगों ने व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए इससे सम्बंधित सुझाव दिए। दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता वाले भारतीय शिक्षा आयोग ने भी यह माना कि राष्ट्र की समृद्धि, औद्योगिकीकरण द्वारा उसका मानवीय एवं भौतिक साधनों के प्रभावशाली उपयोग पर निर्भर है। भारत की विशाल मानव संसाधन शक्ति तब ही लाभप्रद हो सकती है, जब वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम हो। इस आयोग ने व्यावसायिक, प्राविधिक और अभियांत्रिकी की शिक्षा पर बल देते हुए व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में कई सुझाव दिए।

व्यावसायिक शिक्षा दो शब्दों के संयोग से निर्मित है। जिसमें पहला शब्द व्यवसाय एवं दूसरा शब्द शिक्षा है। “व्यवसाय” शब्द जीविकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार के अर्थ में है तथा शिक्षा—संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण युक्त सीखने से है। तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यवसाय संचालन संबंधी जानकारी प्रदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ मानव कार्य की शिक्षा से भी हो सकता है अर्थात् इसमें मनुष्य मस्तिष्क के बजाए हाथों से अधिक काम करता है। जैसे— चमड़े का कार्य, लकड़ी का कार्य, धातु का कार्य, ड्राइंग आदि।

जान डी वी के अनुसार “व्यवसाय परक शिक्षा व्यक्तियों को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाती है, जिससे अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट अपनी विशिष्ट सेवाओं के द्वारा समाज में विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन करता है।”

राधाकृष्णन आयोग (1998) के अनुसार “व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री एवं पुरुष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम पूर्व और उत्तरदायी सेवा के लिए अपने को योग्य बनाते हैं।

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया (1985) में कहा गया है कि “व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक या व्यावसायिक व्यवसाय के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के लिए निर्देश है। यह औपचारिक रूप से व्यापार स्कूलों और तकनीकी माध्यमिक विद्यालयों में या

नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में या अनौपचारिक रूप से बिना नौकरी के आवश्यक कौशल उठाकर प्राप्त किया जा सकता है।”

किसी खास उद्यम के लिए लोगों को तैयार करना ही व्यवसायिक शिक्षा का परम उद्देश्य है। जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए सबके लिए रोजगार उपलब्ध करा पाना सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। वोकेशनल शिक्षा किताबी पढ़ाई अर्थात् ध्योरी पर कम प्रैक्टिकल ज्ञान पर अधिक फोकस करता है। छात्र किसी खास विषय के तकनीक या प्रौद्योगिकी पर महारत हासिल करते हैं।

हमारा देश युवाओं का देश है। आज का परिदृश्य उठा के देखे तो बढ़ती हुए बेरोजगारी सर्वाधिक चिन्ता का विषय है। इसका निराकरण करना केवल सरकार की ही नहीं अपितु आम नागरिक का भी है, और केवल तभी संभव है जब आम आदमी स्कील्ड होकर रोजगार का सृजन करें। सवा सौ करोड़ की आबादी वाला हमारा देश और सभी के लिए रोजगार उगा पाना सरकार के लिए भी नामुमकिन है। बेरोजगारी का अंत तभी संभव है जब आम आदमी अपना उद्यम स्वयं सृजित करें।

केवल 25 प्रतिशत स्नातकों को ही जॉब मिल पाता है क्योंकि बाकि के 75 प्रतिशत प्रशिक्षित होते ही नहीं। देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना। आज हमारे देश में कौशलबद्ध और विशेषज्ञ लोगों की माँग बढ़ रही है। वोकेशनल शिक्षा नौकरी पाने में जॉब सीकर्स की मदद करती है, साथ ही उन्हें उपयुक्त ट्रेनिंग और कौशल प्रदान करती है। भारत का आई टी सेक्टर अपने स्किल के कारण ही विश्व पटल के आकाश का ध्रुव तारा है।

यह बड़ा ही वृहद क्षेत्र है। इसे कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे वाणिज्य, गृह-विज्ञान, पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं पराचिकित्सकीय, अभियांत्रिकी कृषि व अन्य यह विविध प्रोग्रामों जैसे निफ्ट रोलटा मेड, डब्लू-डब्लू आई, एन एच एम आई टी जैसी संस्थाएँ युवाओं को नए-नए प्रोफेशनल स्किल्स को सिखाकर उनका जीवन उन्नत कर रहे हैं।

इसी के अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर उद्योगों के अनुसा रोजगार संबंधी कौशल का सृजन करना है।

हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 : टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (TVET) का शीर्षक वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट रखा गया, जो कई सरी वजहों के कारण बिल्कुल सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत देश में वोकेशनल एजुकेशन का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। क्योंकि इसके तहत देश के तमाम शिक्षण संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में वोकेशनल एजुकेशन को शामिल करने को कहा गया। इसके जरिए बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटी— करीब 2,80,000 से ज्यादा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल और 40000 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को अगले एक दशक में TVET पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों छात्रों का भला हो सके। यह रिपोर्ट देश में TVET शिक्षा प्रणाली की मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के साथ ही इस बात की भी व्याख्या करता है कि देश में NEP को लागू करने में शिक्षण संस्थानों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं यह रिपोर्ट कई तरह के सुझाव और प्रस्ताव भविष्य के लिए देती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत की ज्यादातर आबादी युवा है और 64 फीसदी आबादी काम करने के 15 से 59 वर्ष की उम्र सीमा के तहत आती है। ऐसे में एक बेहतर और पूरी तरह विचार करने के बाद TVET व्यवस्था हमेशा से एक ऐसी आवश्यकता रही है जिसकी मांग कभी कम नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि सबसे बेहतर वक्त में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग को पूरा करने और समावेशी और संतुलित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह शिक्षा जरूरी है। जैसा कि नई दिल्ली यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट का मत है “इसमें दो राय नहीं है कि कोविड 19 महामारी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट और रोजगार को इस स्तर पर प्रभावित किया है जो इससे पहले नहीं देखा गया था। कई मायनों में कोरोना महामारी ने वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण 21 वीं सदी की अर्थव्यवस्था में तेजी से वैश्विक जरूरत बनती जा रही है।”

रिपोर्ट में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित दूसरी चुनौतियों जिनके बारे में बताया गया है उसमें TVE के प्रति समावेशी स्कीकार्यता बढ़ाने की बात कही गई है, खासकर महिलाओं के लिए। इसके साथ ही तेजी से बढ़ रहे डिजिटल विभाजन की भी चुनौतियों से पार पाना होगा और अप-स्किलिंग, री-स्किलिंग और जीवन पर्यन्त

लनिंग के लिए समान अवसर पैदा करने होंगे। वो भी खासकर नए और सामरिक क्षेत्र में जैसे इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन इकोनॉमी को लेकर। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि भारत को अपने स्पष्ट और अस्पष्ट सांस्कृतिक विरासत को संजोने को लेकर बढ़ावा देना चाहिए। इस सक्रियता का यह नतीजा होगा कि, भारत जैसे देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इससे जीविका के साधन उपलब्ध हो पाएंगे और युवाओं में गर्व और स्वामित्व का भाव भी जायेगा।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद मंत्रिमंडल ने कौशल विकास के मद्देनजर मौजूदा नियामक संस्थानों – राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Training - NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency- NSDA) को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training - NCVET) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

NCVET की स्थापना से होने वाले लाभ

- इस संस्थागत सुधार से गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बाजार में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की साख में इजाफा होगा।
- कौशल क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी।
- यह संभव हो जाने से व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यों और कुशल श्रमशक्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके कारण भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के एजेंडा को बल मिलेगा।
- NCVET भारत की कौशल ईको-प्रणाली की एक नियामक संस्था है, जिसका देश में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में संलग्न सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- कौशल आधारित शिक्षा के विचार को आकांक्षी आचरण के रूप में देखा जाएगा, जिससे छात्रों को कौशल आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

- इस उपाय से उद्योग और सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की स्थिर आपूर्ति के जरिये व्यापार में सुगमता होगी।

कौशल आधारित अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण के सभी पक्षों को पूरा करने के लिये एक समेकित नियामक प्राधिकार की आवश्यकता थी और NCVET को एक ऐसे संस्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो उन सभी नियामक कार्यों को करेगा, जिन्हें NCVT तथा NSDA करते रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के अनगिनत लाभ हैं। व्यवसायिक शिक्षा, ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण प्रशिक्षित प्रतिभा का सृजन करने का एक स्वच्छंद स्थिर एवं अपरंपरागत माध्यम है। प्रशिक्षित छात्र इन कोर्सों को करके जमीनी स्तर पर हुनरमंद और काबिल बनते हैं, और अपना अनुभव और काबिलियत अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में भी दिखाते हैं।

यह बेहद कम समय और खर्च में छात्रों को कौशल प्रदान कर उनका जीवन सवार रहीं है। अपने समकक्ष छात्रों की तुलना में वोकेशनल शिक्षा प्राप्त कर एक छात्र औरों की तुलना में कहीं पहले अपना करियर सैटल कर सकता है। जिन्दगी एक रेस की भांति ही होता है, इसमें उसी का घोड़ा जीतता है, जिसकी लगाम एक कुशल, निपुण और अनुभवी जॉकी के हाथों में होती है। जिस देश में जितने ज्यादा स्कील्ड लोग होंगे, वह देश उतनी ही तेजी से तरक्की करता है। जापान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जापान में 97 प्रतिशत लोग स्कील्ड है, यही उनकी ग्रोथ का एकमात्र कारण है। जापान की टेक्नॉलोजी का लोहा पूरा विश्व मानता है।

भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ:-

भारत सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े निर्धन वर्गों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ अधोलिखित है -

1.) उड़ान (VDAAN)

यह कार्यक्रम विशेषतः जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए शुरू किया गया है। यह पाँच साल का कार्यक्रम और यह सूचना प्रौद्योगिकी, बीबीओ और खुदरा क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा और रोजगार मुहैया कराता है।

2.) पॉलिटेक्निक

पॉलिटेक्निक भारत के लगभग सभी राज्यों में चलने वाला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। यह इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषयों में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। पॉलिटेक्निक की शिक्षा गांव-गांव शहर-शहर में प्रचलित है, जो जन-जन तक पहुंचकर छात्रों की राह आसान कर रही है।

3.) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाते हैं। आईटीआई का प्रबंधन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता द्वारा निर्देशित एवं कार्यान्वित होता है।

4.) एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

जून 2011 में लागू किया गया **NRLM** को खास तौर पर **BPL** (गरीबी रेखा से नीचे) समूह में लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न ट्रेडों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को भिन्न-भिन्न उद्यम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे खुद को क्रियाशील एवं रोजगारपरक बनाकर, अपनी और अपने परिवार की आजीविका कमा सकें।

5.) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

यह योजना विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के साथ-साथ पैरामेडिकल, कृषि और वाणिज्य आदि के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गयी है। इसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

व्यवसायिक शिक्षा आज की युवा-पीढ़ी के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं। व्यवसायिक शिक्षा उन्हीं बच्चों के लिए है। व्यवसायिक शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य आम नागरिक के हाथ में हुनर देकर देश की प्रगति में योगदान देना है।

वोकेशनल अर्थात व्यवसायिक शिक्षा किसी भी देश की इकॉनामी का एसेंट होता है। देश की आर्थिक प्रगति वहाँ के वोकेशनल एजुकेशन पर निर्भर करता है। व्यवसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरुदण्ड होता है, जिस पर संपूर्ण देश टिका रहता है।

संदर्भ सूची –

- 1.) <https://www.orfonline.org/hindi/researchputting-vocational-education-centre-stage-in-the-implementation-of-nep-2020/>
- 2.) <https://www.drishtias.com/hindi>
- 3.) <https://www.hindikiduniya.com>